

ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ इंडिपेंडेंस कर का सत्ता अपने हाथ में ले ली है ।

इस लिए मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर कोई बात कहते समय सरकार इस असलियत को अपनी नजर के सामने रखे । आज भी रोडेशिया की आजादी के लिए लड़ने वाले संकड़ों लोग सालिसबरी की जेलों में पड़े हुए हैं, जिन को सहारा देने वाले लोग दुनिया के किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में, नहीं बचे हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को सहारा देने और अफ्रीका की जनता की आजादी की लड़ाई में उस का समर्थन और मदद करने के काम में हिन्दुस्तान और अधिक गतिशील हो और इस के लिये नये कदम उठाये ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाये । कांग्रेस के जिन सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का अपनी तकरीरों में समर्थन किया था, वे अपने विचारों को ठोस रूप देने के लिए अब भी इस प्रस्ताव का पूरा पूरा समर्थन करें और सरकार को यह ताकीद करें कि हम कामनवेल्थ से बाहर निकल आये और अफ्रीका, और खास तौर से रोडेशिया, की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों का पूरा समर्थन करें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put the Amendment of Shri Bibhuti Bishra to the vote of the House.

The question is:

"That in the resolution,—  
for "quit the Commonwealth of Nations forthwith in view of the inaction of the British Government against the illegal minority regime of Ian Smith."

substitute—

"press the British Government to use all possible means, including total economic

sanctions to terminate this illegal regime as well as to urge the Security Council to act under Chapter 7 of the UN Charter and impose total mandatory sanctions against the Smith regime in Southern Rhodesia." (1)

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put the main Resolution as amended by Shri Bibhuti Mishra's amendment.

The question is:

"This House condemns the execution of freedom fighters in South Rhodesia by the illegal regime of Ian Smith and urges the Government of India to press the British Government to use all possible means, including total economic sanctions to terminate this illegal regime as well as to urge the Security Council to act under Chapter 7 of the UN Charter and impose total mandatory sanctions against the Smith regime in Southern Rhodesia." (as amend.)

*The motion was adopted.*

16.34 hrs.

#### RESOLUTION RE. TRADE IN FOOD-GRAINS

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up Shri Mohan Swarup's Resolution. The time allotted is one hour. The next Resolution is also there and Food Debate is coming. I am not inclined to extend the time as far as possible.

SHRI S. XAVIER (TRUNELVELI): Time should not be extended. Otherwise, I may not get my chance to move my Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The discussion on the Demands for Grants of the Food Ministry is coming.

**SHRI S. XAVIER:** I will have some time to move my Resolution if the time-limit is strictly adhered.

**AN HON. MEMBER:** There is another Resolution also.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लरामपुर):**  
वह भी फूड के बारे में है।

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** If that has also secured the ballot, what can I do?

**श्री मोहन स्वरूप (सीलीभीत):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“इस सभा की राय है कि अनाज के व्यापार का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।”

आप जानते हैं कि देश के 5,58,000 गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग खेती करते हैं और

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का सम्बन्ध खाद्य और कृषि मंत्रालय से है, लेकिन इस मंत्रालय का कोई भी मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है।

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** He will be coming in a minute.

**SHRI M. A. KHAN (Kasganj):** There is no quorum.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** The bell may be rung—The bell may be rung a second time.—Now there is quorum.

Shri Mohan Swarup.

**श्री मोहन स्वरूप :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जहाँ के 5 लाख 88 हजार गांवों के अधिकांश लोग खेती का व्यवसाय करते हैं और खेती से ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तो जाहिर है कि वह अपनी उपज को बेचेंगे और धान वाले

पैसे ले अपना काम चलाएंगे। लेकिन व्यापार तो व्यापार की व्यवस्था है इस वक्त वह एक अजीबोगीब है। व्यापार कुछ ऐसे विशेष लोगों के हाथों में है जो कि गल्ले को अपने मनमानी ढंग से बेचते हैं और उसको स्टोर करते हैं। उसको ख़र्च चाहे तब बेचते हैं, ख़र्च चाहे तब खरीदते हैं। तस्करी करते हैं उस गल्ले का, उसमें मिलावट करते हैं और दुनियाँ भर का ऐसा कौन सा काम है, कौन सा पाप है जो कि यह व्यापारी नहीं करते? ख़र्च चीन और पाकिस्तान के साथ संवर्ध चल रहा था तो मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में कुछ लोगों ने चीन को नेपाल के द्वारा चीनी और गल्ले बेचा। उपाध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं इससे अधिक और देशद्रोह क्या हो सकता है? अभी रूरल क्रेडिट कमेटी ने एक सर्वेक्षण किया था 1950-51 में तो उन्होंने बताया था कि गांव के लोगों के लिये 750 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ऋण लेने के सिलसिले में। उसके बाद वह आवश्यकता फिर 1000 करोड़ और 1200 करोड़ से ऊपर बढ़ गई 1958-59 में और अब तो शायद वह 2000 करोड़ रुपये से अधिक है। आप समझते हैं कि किसान या तो अपने गल्ले पर आधारित है या ऋण कहीं से पाये उस पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में जब कि उनका इस तरह से शोषण हो रहा हो, और यह जो व्यापारी हैं इनका एक ही काम है कि किसान से सस्ते मूल्य पर गल्ला खरीदें, जब कि किसान पास गल्ला होता है तो दाम गिर जाते हैं और जब कि किसान के घर से गल्ले व्यापारी के घर चला जाता है तो ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता उसके मूल्य में घटे शुरू हो जाते हैं, तो उनका एक ही काम है कि सस्ते दर पर गल्ला किसान से खरीदें और उपभोक्ता को महंगे दामों पर दें। इससे न तो किसान को ही राहत मिलती है और उपभोक्ता का गला अलग से कटता है। जाहिर है कि खाद्यान्न में मुनाफा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। उनका जो खर्चा होता है, लाने ले जाने का, स्टोर करने का

घर को कुछ उसमें घाटा हो जाय, चूहे खा जाय या और तरह से नुकसान हो जाय उसको निकाल कर 5 प्रतिशत से अधिक मुनाफा नहीं होना चाहिये। लेकिन आजकल वह 50 प्रतिशत और कभी कभी तो सौ प्रतिशत तक मुनाफा कमाते हैं। 70 रुपये की बोरी रोहू की खरीदी गई सन् 66 में और सन् 67 में आकर 150 रुपये पर बेची गई। तो करीब करीब सौ प्रतिशत तक मुनाफा यह कमाते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों का शोषण हो रहा है, किसान का भी और उपभोक्ता का भी। इसलिये सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिये। मैंने सुझाव दिया है कि यह व्यापार इनके हाथ से ले लिया जाय और एक ऐसी संस्था बनाई जाय जो कि इस कार्य को अपने हाथ में ले सके। खाद्यान्न का जो पिछला साल गुजरा है वह बड़ी परेशानी वाला गुजरा है। इस साल खाद्यान्न की स्थिति कुछ सुधरी है। इस साल 90 मिलियन टन से ले कर 100 मिलियन टन तक गल्ला इस देश में होगा। ऐसी स्थिति में हम अपना खाद्यान्न का जो कारोबार है उसको अगर अच्छे ढंग से चलायें तब जाय इसके कि इन लोगों के हाथ में यह रहे तो बहुत कुछ हालत सुधर सकती है।

आप जानते हैं कि बाजार तीन चार तरह के होते हैं। एक गांव का बाजार होता है जिसमें कि हफ्ते में एक या दो बाजार होते हैं। इसके बाद कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो घोड़े से या गाड़ी से गल्ले ले जाते हैं और फिर मंडी होती है। मंडी के बाद एक होलसेस मार्केट होता है जो कि जिले के स्तर पर होता है। इन सारी चीजों में शुरू से लेकर आखीर तक करप्शन चल रहा है। जब होलसेस मार्केट में किसान गल्ला ले कर जाता है तो वहां आड़तिये होते हैं, दलाल होते हैं। दलाल अपनी दलाली वसूल करते हैं, आड़तिये अपनी आड़ती वसूल करते हैं, तौलने वाला भ्रमण अपनी मजदूरी वसूल करता है। इस तरह से चारों तरफ से उसका वहां पर शोषण होता है शुरू से लेकर

आखीर तक। आसमय आ गया है कि उसको खरब करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में कई चीजें हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि एक नेशनल संस्था ऐसी बनानी चाहिये और एक बकर स्टोक बनाना चाहिये। एग््रीकल्चर प्राइज कमीशन की रिपोर्ट और एक फूड ग्रेन पालिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है जो 1966 में हुई है और वह 1967-68 में अभी हाल ही हुई है। इन कमेटीज की रिपोर्टें हमारे सामने आई हैं। इनके अनुसार यह कहा जाता है बकर स्टोक हमारा बनना चाहिए और मिलियन टन का कम से कम होना चाहिये। इसके बाद कहा जाता है कि प्रोक्वोरमेंट भी होना चाहिये। प्रोक्वोरमेंट भी कहते हैं कि 8 मिलियन टन हर साल हो जाना चाहिये। वह कहते हैं कि डिकेइस तक, काफी भरसे तक गल्ले का भाव इस तरह से रहेगा तो उन क्षेत्रों प्रोक्वोरमेंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ इन्टर-स्टेट मूवमेंट भी एक आवश्यक बात समझी गई है। लेकिन उस में भी रुकावट पड़ रही है क्योंकि फूड कारपोरेशन एक है हमारे यहां। वह काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। और उसी के साथ साथ जॉनिंग सिस्टम है जिस की वजह से इन्टर-स्टेट गल्ले का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अभी अभी उत्तर में एक बड़ा जोन बनाया है लेकिन दक्षिण में या मध्य भारत में और कहीं भी बड़ा जोन नहीं है। उत्तर प्रदेश को भी जो बड़ा जोन अभी बनाया है पंजाब हिमाचल प्रदेश हरयाणा वगैरह का उस में नहीं लिया गया है। तो इस तरह से भी जो इन्टर स्टेट मूवमेंट है गल्ले का उस में रुकावट पड़ रही है, जोनल सिस्टम की वजह से इसके बाद एक प्राइम फिक्सेशन कमेटी बनी हुई है फूड मिनिस्ट्री के अन्तर्गत जो कि प्राइस का सर्वेक्षण करती है और कीमतों का निर्धारण करती है। लेकिन वह भी कुछ सक्रिय तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही है। तो यह जो चीजें हैं जिन की आज आवश्यकतायें हैं उन की पूर्ति करने के लिये

[श्री मीड़न स्वराज]

कोई एक संस्था ऐसी नहीं है हमारे पास जो इन सारे कामों को इकट्ठा कर के सामूहिक तरीके से कर सके। मेरा सुझाव है कि हमारे यहां जो फूड कारपोरेशन है उस का कार्यक्रम विस्तृत किया जाय। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस का दफ्तर मद्रास में है जो कि देश के दूसरे सिरे पर है और उस की जो कार्यशैली अब तक रही है वह विफल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उस को ठीक तरीके से कार्य करने के ढंग पर लाया जाय। उस का दफ्तर चाहे मध्य भारत में या उत्तर भारत में जहां कहीं मुनासिब हो वहां रखा जाय, देश के एक सिरे से हटा कर बीच में रखा जाय तो बेहतर है। इस के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो सारी चीजें मैंने बताया इन सारी कार्यवाहियों को करने के लिए उस को उत्तरदायी बनाया जाय। मैं चाहता हूँ कि उस का दफ्तर जोनल दफ्तर बने। हर राज्य में बने और उसी के साथ साथ हर जिले में उस को विस्तृत कर के उस का दफ्तर बनना चाहिये। उस की कार्यशैली इस तरह की होनी चाहिये, जैसी कि गन्ने के महकमे की होती है। गन्ने का जो विभाग है, वह गन्ना भी देता है, किसानों को कर्जा भी देता है, साथ ही साथ वह गन्ने को ले कर मिलों को भी देता है, ये तीन काम करता है। इसी तरह का फूड कारपोरेशन का कार्य होना चाहिये, वह किसानों से गल्ला घसूल करे, उन को मुनासिब कीमत दे, उपभोक्ताओं को भी मुदानिब ढरों पर गल्ला मिल सके इस बात की वह गारन्टी करे। इस के लिये फूड कारपोरेशन को सक्रिय बनना होगा।

मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ जो नेशनल सीड कारपोरेशन है, उस को भी इसी में जोड़ कर इन की एक संस्था बना दी जाय। फूड कारपोरेशन और नेशनल सीड कारपोरेशन दोनों मिल कर इस कार्य को उठायें। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाय तो जो बातें मैंने यहाँ पर पेश की हैं, चाहे प्रोक्वियरमेंट का सवाल है, बफर स्टॉक का

सवाल है, इन्टर स्टेट मूवमेंट का सवाल है इन सब के लिये इस प्रकार की संस्था अच्छी तरह से काम कर सकेगी।

एक चीज और है जो कि बिचारणीय है। प्राइस फिक्सेशन बोर्ड आज तक कोई नहीं बना है। यह बहुत ही आवश्यक है कि इस तरह की संस्था बने जो कि गल्ले के मूल्य का निर्धारण करे। इस में किसानों के भी प्रतिनिधि हों, गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि हों, और चूंकि हम नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, इसलिये नेशनल सीड कारपोरेशन और फूड कारपोरेशन के भी प्रतिनिधि हों और वे बैठ कर तीन महीने के हिाब से गल्ले के मूल्य का निर्धारण करें कि मई-जून, जुलाई में यह भाव होगा, उस के बाद आगे आने वाले महीनों में यह होगा, क्योंकि गल्ले के साथ सप्लाई एण्ड डिमाण्ड का प्रश्न भी आता है। उस के बाद गल्ले का ग्रेडिंग किया जाय—फर्स्ट, सैकेंड और थर्ड—तीन ग्रेडिंग होंगे, इसके अनुसार जब गल्ले के भाव का निर्धारण हो जायगा, तो किसान इस बातके लिये बड़ी खुशी से तैयार हो जायेगा कि वह अपनी उपज को खेतों से ले जा कर फूड कारपोरेशन को जो कि जिले में होगी, दे दे।

इसी के साथ साथ रिबेट की भी व्यवस्था होनी चाहिये। किसान को दो परसेंट या तीन परसेंट रिबेट गल्ले पर मिल सके। इस से उस को प्रोत्साहन मिल सकेगा और वह बड़ी खुशी से गल्ले को दे सकेगा। मैं समझता हूँ कि गल्ले के व्यापार को अगर इस स्तर पर लाया जाय, तो प्रोक्वियरमेंट का जो सवाल है, वह हल हो जाता है, बफर स्टॉक बन सकता है, किसान को अच्छा मूल्य मिल सकता है और साथ ही साथ उपभोक्ता को भी खाने के लिये गल्ला ठीक दामों पर मिल सकता है। इस व्यवस्था से, आज जो शोषण हो रहा है, जिस की वजह से सारे लोग—चाहे उपभोक्ता हों

या किसान—पीड़ित हैं; परेशान हैं, वह दूर हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घ्राप को बताऊँ कि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उत्पादित की हुई वस्तु का भाव स्वयं निर्धारित नहीं करता है, बल्कि उस का निर्धारण खरीदार करता है। प्राज जो चीजें मिलों में उत्पादित होती हैं, चाहे बन्म बनते हों, चाहे जूते बनते हों, वहाँ पर निर्माता उन चीजों के दाम निर्धारित करता है, लेकिन किसान अपनी उत्पादित चीजों का दाम स्वयं निर्धारित नहीं कर पाता है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब इस का अन्त होना चाहिये। जो बातें ब्रिटिश शासनकाल से अब तक चली आ रही है, उन का खत्म कर के एक नई मूरत पैदा करनी चाहिये जिस से कि हमारा देश तरक्की कर सके।

गल्ले के बारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि सरकार इसको स्वीकार करेगी और इस के राष्ट्रीयकरण की तरफ सक्रिय पग द्वायेगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:

"This House is of opinion that trade in foodgrains be nationalised immediately."

As I have said, one hour only has been allotted for this because the subject of the next Resolution is also almost the same. Therefore what I suggest is that we will accommodate a few speakers on this and a few on the next one. Each Member will have just five minutes.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would begin by saying that the title of this Resolution is incorrect because, as our hon. Member proceeded to explain, his idea of nationalisation is 4 million tonnes of buffer stock and 8 million tonnes of foodgrains supply to the public. This

is a little more than the present system and our friend, therefore, has not really advanced as far as the Communist to suggest total nationalisation of trade. But even this partial trade in grains has done no good to anyone. One has to inquire which class has benefited from Government's purchase of foodgrains. As far as the cultivator is concerned, though I do not see many representatives here, they have the grievance that they are paid only a fraction of the price at which Government sells and at which the market sells the grain which is bought from them. Is it fair, as our hon. Member considered that he is speaking for the cultivators, that they should be deprived of a proper price?

The second class consists of the traders. He has very rightly condemned them. I do not know how many traders are represented here.

SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI (Kharagone): Only you are there.

SHRI LOBO PRABHU: I am not a trader.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): You are their advocate.

SHRI LOBO PRABHU: I am the advocate of honest traders and of honest people.

The question is, if today the traders are dishonest—they are—it is because there is no competition. Government itself is to blame that has reduced the quantity of food supply coming to the market. Government itself is to blame that prices are always rising. So long as prices rise there is a tendency to hoard, to profiteer and even to black-market. So, if there is anyone to be blamed for the dishonesty of the trade, it is the Government.

The third is the class of consumers. Consumers can be placed in two categories—the rich like our friends and the poor like our friends there.

**SHRI SHEO NARAIN:** Are you poor?

**SHRI LOBO PRABHU:** There are no rich men here.

As far as the rich are concerned, controls do not touch them very much because they are able to purchase whatever they want; they are only corrupted. Controls corrupt the rich because they give a scope, a free play to the power of their money. As far as the poor are concerned, I would like people to understand what it means to stand for hours in a queue which one could find at any time in the past when there was genuine scarcity of grains. For them to lose a day, sometimes even more, for a handful of grain, I think, is one of the tragedies of our administration, something about which the Food Ministry should be thoroughly ashamed that not only have they got to wait that long and pay a price much higher than what has been paid to the cultivator but they have to get grain which in a good part is not grain at all but is sand and stone. So, the poor are the sufferers here again.

Therefore, if our friend thinks that nationalisation is going to do good to anyone, he is not thinking of any people in this country except perhaps the smugglers and the corrupt government servants.

He has, luckily for this House, proposed the abolition of zones. He has proposed also that inter-State movement should be free. That is certainly an advance on the thinking of Government on this subject. Government has only enlarged one zone. Government should enlarge all zones. Shri Somani, no doubt, will speak more about it. But I would just like to ask this of Government: What is the benefit of these zones? Is it their interest to create pockets of scarcity, vacuums to which the grain is sucked at a rate and at a price which is always rising? If the idea of Government is to raise prices, then zones and inter-State bans have a purpose. If

not, they are only in favour of smugglers who, at every border, are able to bring the grain, pay the police and get sometimes, as in my district, across to Kerala, a price twice or thrice that they pay for it.

17 hrs.

Let us just think in terms of abolishing the zones. If prices fall, zones will become redundant because there will be pressure, I have no doubt my hon. friend, from Haryana, will press for abolition of zones because they are unfair to the growers that the prices should be restricted on one side of a line. If prices fall, zones will go. If prices do not fall, zones will stay and prices will rise further. I for one see that the prices will fall and the fall in prices is going to have consequences which have not been considered in this House. If Government keeps a large stock, and they are providing Rs. 720 crores for the grain trade, if the prices fall by anything like 10 per cent on the prices paid by Government, there will be a loss of Rs. 72 crores. This loss to the Government is a loss to the people. Government pays nothing from the pockets of Ministers. Government pays from the pockets of the people. Therefore, whether the prices rise or fall, controls are bad. Nationalisation of trade is bad. Free competition is the passport to a better order of things.

17.02 hrs.

[**SHRI G. S. DHILLON** in the Chair]

**SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI** (Bhubaneswar): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Minister at least some points on which I would like to be enlightened.

The Food Corporation of India is doing a very good job. But I would urge upon the Minister to let us know this. In recent times, there has been some thing going on in the Food Corporation itself which was brought to

the notice of the public by its ex-Chairman. Today, the Food Corporation cannot afford to function itself as a body dominated by certain bureaucrats because it is now competing with a large number of private traders. During the last so many years, the private traders in foodgrains have exploited the producers of foodgrains which my hon. friend, Shri Mohan Swarup, has tried his best to bring to light by moving this Resolution

The Food Corporation's activities have been expanded and it has gone over to as many as 14 States. It is a good thing. In Haryana, in the last few months, there was a distress sale of wheat. In the beginning, the Haryana Government did not like to invite the Food Corporation. But in later period, when there was a distress sale, when the wheat prices in Haryana which varied between Rs. 100 to Rs. 115 a quintal at the time of the harvest and which were expected to rise further to Rs. 124 a quintal, when these crashed immediately during the lean period and came down to Rs. 70 to Rs. 75 a quintal, the Haryana Government sent an SOS to the Food Corporation asking them to enter the market immediately. Then, the Food Corporation entered the market and saved the situation.

Here, the question arises that the Food Corporation, according to the present calculations, would require a working capital of nearly Rs. 200 crores at the peak operation during the season. The Food Corporation had fixed a target of procuring 6 million tonnes this year, and the procurement target was fixed at 5 million tonnes by March, 1968. We would like to know from the hon. Minister whether really this procurement target, by March, 1968, of five million tonnes has been fulfilled. I know that it has not been fulfilled. I have got reports from certain State Governments—and I can bring it to the notice of the hon. Minister—that the procurement has failed. Let me cite the instance of that Government, which is run by the Party

of Mr. Lobo Prabhu, i.e., the State Government of Orissa, where Swatantra is ruling. The hon. Minister will please let us know whether the hon. Chief Minister of Orissa has already informed the Government of India that the procurement in Orissa is not progressing satisfactorily because the millowners are not co-operating with the Food Corporation there. I hope, the hon. Minister will agree at least that such a letter has come from the Chief Minister to the Ministry here. If this is the position, then we would like to know what steps Government of India are taking to activate procurement in that State and in such other States where the millowners are not co-operating.

One more point and I will have finished and that is with regard to one anomaly that we have. India is trying to win the battle of economic independence on all fronts and also on the food front. But I am completely surprised over this. India was importing 11 million tonnes of foodgrains when there was drought, and India is now importing nearly 8 million tonnes of foodgrains when according to Government of India this is one of the bumper crop years in India and that the production has gone up from 95 million to 100 million tonnes. How is it that the more the production increases, the more the import also increases? How is it that a procurement, in a bumper crop year of 95 or 100 million tonnes, has been fixed at only 5 million tonnes by March, 1968 whereas the Agricultural Prices Commission suggested a procurement target of 8 million tonnes? I do not want to take much time of the House. I would request the hon. Minister to enlighten us on this, and I hope that the hon. Minister will try his best to help the Food Corporation of India in expanding its activities. Whatever difficulties or whatever deficiencies may be there, it is because that the Food Corporation has come in, that at least the producers are getting a better price today. A total trade in foodgrains of about Rs. 2,600 crores is controlled by private traders, and I would

[Shri Chintamani Panigrahi]

urge on the hon. Minister that the Government of India should gradually increase the scope of the Food Corporation of India, so that in the near future, the trade is nationalised. This is one of the ten points that the AICC has accepted; the Congress has given a promise to the people that, in the near future, more and more trade will be nationalised, in the sense that it will be in the public sector, and the profiteering, hoarding and black-marketing resorted to by the private traders, should end and the producer should get the reasonable price for his produce.

श्री बेरीशंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, जिस समय दो वर्ष के सूखे के बाद और भुखमरी के बाद देश में कुछ भन्न पैदा हुआ है और लोग यह आशा करते हैं कि रोजनल जोन्स हटा दिये जायेंगे जिनकी वजह से आज देश के लोगों को जितना भन्न मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है, उस समय श्री मोहन स्वरूप जी का यह प्रस्ताव कुछ ऐसा है जिसका कोई भ्रम समझ में नहीं आता । उन्होंने कहा है कि हमारे 5 लाख 58 हजार गांवों में खाद्यान्न हम किस तरीके से पहुंचाये यह एक समस्या है । लेकिन मेरे वह मित्र यह भूल गये कि ये गांव ही हैं जहां भन्न पैदा होता है । अगर हम भन्न के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो सारा भन्न गांवों से खिच कर शहरों में भ्रायेगा जिससे लोगों की तकलीफें घटने के बबले बढ़ जायेंगी ।

अभी देश में पाशियल कंट्रोल की स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ भनाज किस तरह बर्बाद होता है और लोगों तक नहीं पहुंच पाता । कलकत्ते में हमने देखा है और अमृत बाजार पत्रिका में कुछ दिन पहले यह रिपोर्ट निकली थी कि बाहर से अमरीका से जो गेहूं आता है उसका करीब-करीब 10 प्रतिशत: हिस्सा धू की ब्रूस बला आकर बर्बाद हो जाता था । इसका

कारण यह था कि वहां लोगों को उसके प्रति मोह नहीं था । सरकारी कर्मचारी जोकि उसमें काम करते थे उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं थी कि भनाज सड़ ब बर्बाद हो रहा है । उन्हें उसके द्वारा नुकसान होने की कोई चिन्ता नहीं थी और पनाह नहीं थी कि यह नुकसान किसका हो रहा है ।

भनाज के राष्ट्रीयकरण की आज जो हाउस में चर्चा हो रही है अगर इसकी मांग भी बनर्जी करते तो वह सभ्य में आ सकती थी । कम्युनिस्ट मित्र भी ऐसी मांग करते तो मैं उनको भी समझ सकता था क्योंकि वे लोग सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं । उत्पादन का राष्ट्रीयकरण हो, भन्न के व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, कपड़े के व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण हो लेकिन मैं इस तरह के एक ऐसे पाशियल राष्ट्रीयकरण की बात को नहीं समझ सकता हूं क्योंकि इससे देश में कितनी ही परेशानियां बढ़ जायेंगी और इससे कितने लोगों के कष्ट बढ़ जायेंगे जिसका कि कोई हिसाब नहीं है ।

वांछनीय तो यह है कि कोई भी प्रस्ताव हो कोई भी कार्य हो उसमें लोगों का और जनता का हित होना चाहिये । अब मेरे माननीय मित्र अपने इस प्रस्ताव से किन लोगों का हित करना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

हम ने आज कलकत्ते में भनाज की स्थिति को देखा है । कलकत्ते में फूड कंट्रोल है और जब हमारे यहां रोटी का अभाव था तो ब्रैंड होटल और ग्रेट ईस्टर्न होटल के सामने 2, 2 मील की लम्बी कतार खड़ी देखते-देखते और उस हालत को देख कर कलेबा मुंह को घाता था । मुझे इस बारे में एक कहानी याद आ रही है कि कोई एक हमारे मित्र जोकि यहां से आ गये थे जब वह वहां एक कसी दम्पति के यहाँ गये और उन्होंने घर में मीठूप लकड़के से पूछा कि तुम्हारे पिता भी कहाँ हैं तो उसने जवाब

दिया कि वह स्पेस में है। जब उस लड़के से पूछा गया कि उसकी सतता जी कहां है तो उसने जवाब दिया कि वह रोटी लेने गई है। यह पूछे जाने पर कि उन दोनों में से पहले कौन प्रायेगा लड़के ने जवाब दिया कि पिता जी पहले प्रायेगे माता जी पीछे प्रायेगी। अब रूस में जहां नेशनलाइजेशन का या राष्ट्रीयकरण का इतने दिनों से प्रचार हो रहा है और उस पर व्यावहारिक रूप से प्रमल किया जा रहा है जब वहां यह प्रवस्था है तो हम लोगों की क्या उस हालत में क्या प्रवस्था होगी यह मेरी समझ से बाहर की चीज है।

महापति महोदय, अभी हमारे यहां कई क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण हुआ है। बिहार और बंगाल में बस ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया गया है। जो बसें वहां चलती हैं वे करीब-करीब सब राज्य के कंट्रोल के अन्तर्गत हैं। लेकिन आज वहां करोड़ों रुपये की सरकारी पूंजी लगा कर भी क्या उसमें प्राय होती है और क्या उसमें बचत होती है? मैं बंगाल की बात जानता हूँ बिहार की बात जानता हूँ। दोनों जगह इस बस ट्रान्सपोर्ट के नेशनलाइजेशन के अर्थ में सरकार को नुकसान हो रहा है। यहां पर अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं वह इस बात को जानते होंगे कि हमारे सरकार कलकत्ते में और दूसरी जगह जो बस चलाते हैं वह 10-12 हजार रुपये साल में कमा लेते थे और अपने परिवार अर्थात् का पालन करते थे लेकिन जब से इन सरदार लोगों को हटा करके यह बसों का राष्ट्रीयकरण किया गया वहां करीब-करीब 900-1000 बसों का फ्लीट और कंट्रोलों की पूंजी उसमें सरकार ने लगाई तो आज उसमें नुकसान हो रहा है। आज प्राय उन बसों का सकल खर्च, वह टूटी फूटी हैं, फिस्ती की खिड़की नहीं है तो फिस्ती का दरवाजा नहीं है। ऐसी-इस-उसके इस बस राष्ट्रीयकरण उद्योग की वहां पर हो रही है। ऐसी प्रवस्था में अगर हम आजाद का भी राष्ट्रीयकरण करते हैं तो

मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि लोग भूखों मर जायेंगे।

अभी हमारे माननीय मित्र ने व्यापारियों में वरदान की चर्चा की है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि व्यापारियों में भ्रष्टाचार नहीं है। व्यापारियों में भ्रष्टाचार है लेकिन उनमें उस भ्रष्टाचार की वजह क्या है क्या इस ओर भी आप ने ध्यान दिया है? अगर आप यह कंट्रोल हटा देंगे तो भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे कहने के लिये क्षमा किया जाय कि इन 20 वर्षों में कंट्रोल की वजह से अपराधों की संख्या बढ़ी है वरना व्यापार वह चीज है कि अगर ट्रेड फ्री कर दी जाय और कोई कंट्रोल न रहे तो व्यापारियों में एक फी ऐंड हैल्दी कम्पटीशन पैदा होगा और वह कम से कम प्राफिट पर अपने माल को कम्प्यूर्स को बेचेंगे।

आज आप कहते हैं कि राजस्थान में वना 25 रुपये मन मिलता है जबकि हमारे यहां बिहार में सतु खाने के लिये लोगों को चने की आवश्यकता होती है तो वही वना हमारे यहां 80-90 रुपये मन मिलता है। इस तरह से अधिक मुनाफा कमाने की कुछ लोगों की टैन्सी है उसको प्राय रोक नहीं सकते हैं। वहां राजस्थान में 25 रुपये मन वना मिलता है और वह 25 के बदले में उसे बिहार में 88 रुपये मन में बेचते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा अगर आप इसमें फी कम्पटीशन कर दें तो होगा यह कि कुछ लोग 25 रुपये मन में वहां से लेंगे और अपना खर्चा प्रादि मगा कर उसे 35 रुपये में बेचेंगे, कुछ 40 रुपये में बेचेंगे और हो सकता है कि कोई प्राई खर्चा और कुछ मुनाफा लगाकर 38 रुपये मन में बिहार में बेच देंगे। कुछ 36 रुपये में ही बेच देंगे। अब इसमें भ्रष्टाचार का मवाल कहां उठता है? भ्रष्टाचार अभी होता है जब आप कहते हैं कि हम राजस्थान में 25 रुपये मन वना खरीदते हो तो उसे 25 रुपये पर ही क्यों नहीं बेचते हो। इसलिये जाहिर है कि जितने में

[श्री श्रीमोहनकर शर्मा]

उसने खरीदा है उतने में कैसे वह बेच सकता है ? उसका खर्चा लग जाता है और फिर वह प्रंधा जो करता है तो चार रैसे कमाने के लिये ही तो करता है । इसलिये जैसा मैंने पहले कहा अगर आप करप्शन को हटाना चाहते हैं तो सब से पहले कंट्रोलों को हटाना पड़ेगा । स्वामी विवेकानन्द जी ने एक बार कहा था : "यू कैन नौट लेजिस्लेट फोर वरबू" । आप अच्छे काम के लिये कोई कानून नहीं बना सकते हैं । अच्छे काम के लिये आप को एक वातावरण तैयार करना होगा । अगर आप खाद्यान्न के व्यापार से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो सब से पहले आप को कंट्रोलों को उठाना होगा । सब से पहले जोनल मूवमेंट जो व्यापार का है उसको हटाना होगा फिर आप देखिये कि कहां भ्रष्टाचार है और कहां अनाचार है ?

**SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) :**  
Mr. Chairman, Sir, I whole-heartedly appreciate the spirit in the Resolution and congratulate Shri Mohan Swarup for bringing forward this outstanding resolution. This is an old demand and age-old demand of the poor peasantry, who have been so much pressed and oppressed by vested interests, by feudal lords and big landlords since time immemorial. You must remember. Mr. Chairman, that peasantry in our country are a class of absolutely exploited people. They are the fore-runners and yet they have always been relegated to the background and no avenues of development or progress were made available to them. In this era, when we are free, there is a genuine demand that the peasantry, the poor farmer, should be given the proper place. And that proper place can only be given if they get their due, for their produce. It is an admitted fact. Whatever the peasant is investing, he is not getting his proper return. This issue involves fundamental issues of justice, fairplay, equity and ethics also. Why should a man who puts such a hard labour day in

and day out, in season and out of season, in chilly winter and scorching heat, who is down to the earth and who has done strenuous and hard work, be deprived of his labour? A man who is putting his labour must get due return for that.

It is very important that this particular sphere of marketing of his foodgrains should be taken note of by the Minister in charge of Food and Agriculture. It is good luck, Sir, that a progressive farmer is at the helm of affairs. Mr. Shinde himself is a farmer, and our Cabinet Minister, Shri Jagjiwan Ram is a farmer, and both of them come from Bihar, the core of the peasantry. I am proud of this, Sir. And much of our hope is pinned on them. It is high time that they appreciate the crying need of the country. They will go down in history as the saviours of the poor peasantry, by taking up the cause of nationalisation of food trade.

The marketing centres have become forums of loot, forums of exploitation and forums of butchery of the poor peasantry to deprive them of whatever they are entitled to. The middlemen earn not only 100 per cent but even 200 or 300 or 500 per cent of what they are investing as profits. These middlemen must go. I am not against the petty shopkeepers or the small people who are poor people. But I am referring to the class of hoarders which has come to stay. Their main job is to create scarcity in the country by acting as parasites on the blood of the poorer sections of society, and they are piling up huge profits.

My request is that the peasant must get his due return. So far as the prices are concerned, he should get better prices, and whatever he wants to purchase such as cement, sugar, iron, cloth, fertilisers, electricity etc. should be made available to him at reasonable rates because he is being

burdened with innumerable taxes, canal rates, *chaara jagaan*, local rates electricity tax and so on.

This is the time when in free India people like the present hon. Minister are in power and when a party like the Congress is in office, whose aim is to bring about democratic socialism and this is the time when they should do something for the peasantry. 80 per cent of the population of our country is in rural areas, and it is heralded by the peasantry and they should be made citizen No. 1 in the country. They should be affluent and they should be free from the scourge of want and exploitation.

I wholeheartedly support the resolution moved by my hon. friend.

SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam): The middlemen in the food trade are appropriating the bulk of the profits in foodgrains trade. They accumulate huge profits by purchasing foodgrains at a lower price and selling them at higher prices when the prices go up. The poor peasants who are the actual growers of the grains get lower prices and the consumers have to pay higher prices when they purchase from the market.

That is why we are demanding nationalisation of the food trade. The Central Government are not sincere in approaching this problem and solving it. They started the Food Corporation of India with a capital of Rs. 100 crores. But they have procured only 3 per cent of the needs of the total population of the country as a whole. There has been no co-ordinated approach with regard to the implementation of the national food policy. They have been discussing about a national food policy for the last so many years but nothing has emerged out of it so far because they are not ready to purchase or procure the surplus food from the hoarders and swindlers who are having it in the surplus States. The result is that the deficit States are suffering, and they are in an acute position and are in a starving condition.

The Centre is also using food as a weapon in politics. I am not going to argue about such things because this House has already discussed this on many an occasion. The instances of Kerala and Bengal have already been quoted here. I am not going into all that now.

If Government do not nationalise the food trade, immediately the people will think that Government are siding with the profiteers, blackmarketeers and landlords.

SHRI PILOO MODY (Godhra): The debate on this resolution must conclude at 5.30 p.m. There are two more resolutions after this.

MR. CHAIRMAN: This resolution was moved at 4.40 p.m. May I know how long the hon. Minister would like to take?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNA-SAHIB SHINDE): About 8 to 9 minutes.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Shashibhushan Bajpai.

श्री शशि भूषण बाजपेयी (खारगोन) : सभापति महोदय, मैं श्री मोहन स्वरूप जी को, जो यह प्रस्ताव लाये हैं, मुबारकबाद देता हूँ, खास तौर 'इसलिये कि पी०एस०पी० के एसे ही नेता मही नेतृत्व दे सकते हैं। मुझे यह आशा है कि माननीय सदस्य इसी प्रकार के प्रस्ताव हमेशा लाते रहेंगे ताकि देश में जागृति बढ़े।

जहाँ तक इस देश में भ्राड़तियों की कल्चरल बैंकप्राउड का सवाल है, जब तक यह भ्राड़तिये लोग इस देश से समाप्त नहीं किये जाते तब तक वह कोई भी दूसरा काम करने के लिये तैयार नहीं होंगे। नतीजा यह होता है कि कई लाख लोग सिर्फ इसी बात में लगे रहते हैं कि किस तरह से गाँव वालों को लूटें और किस तरह से उनसे भनाज लेकर रख लें तथा महंगा से महंगा बेचें। उनके बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं

## [श्री-मणि भूषण बाजपेयी]

लगाते। पढ़ने लिखने के बाद भी, बी० ए० एल० एन० बी० करने के बाद, डाक्टरी पास करने के बाद भी वह फिर आड़तियों की दूकान पर घा कर बैठ जाते हैं। जब तक उनको इस तरीके से नहीं मारा जायेगा तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। बीमा हमारे एक जन संघ के लिए बे कदा; किसानों-अंतरिक्ष में चला गया और मां रोटी लेने चली गई। वह रोटी के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, अंतरिक्ष में कोई नहीं जा सकेगा। अगर इस देश के लोगों को अंतरिक्ष में भेजना है तो इन लाखों आदमियों को एक दूसरी दिशा में लाना होगा।

राष्ट्रीयकरण के लिये कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। जैसे हमारी गड़म मिल्म है। इनका तैयारलाइजेशन होना चाहिये क्योंकि वह बहुत काफी स्ट्राक कर लेती हैं, बैंकों का भी तैयारलाइजेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि बैंक अनाज के लिये बहुत पैसा देते हैं और अनाज रखवाते हैं। कई बार तो यह होता है कि जिन चीजों के लिये कहा जाता है कि बैंक में हैं, जिन चीज के रखने की एंट्री होती है किताबों में बह नहीं रखी जाती है, बल्कि दूसरी चीजें होती हैं। आज जो बड़े बड़े जागीरदार और राजे महाराजे गाँवों में हैं वह बड़े बड़े बेघर हाउसेज तो नहीं बना सके, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी गढ़ियाँ हैं, उनके बड़े बड़े महल हैं, जो कि इस काम में आते हैं और गाँवों का सारा अनाज उनमें रख लिया जाता है। जब तक इन राजे महाराजों की शक्ति कम नहीं की जाती है, तब तक हमारा काम नहीं चल सकता। आज भी इस देश में आड़तियों को बैंक बैंकों में लाना कर इन राजे महाराजों के हथों में लाने लगा है।

आज हमारा सीधे कारपोरेशन बना हुआ है, उसमें देश के एक बहुत भागे हुए मेला बेघर-मैन बनाये गये। उसी तरह से फूड कारपोरेशन में लोग अन्धकार की छटा कर सकते

हैं, उनको लाना चाहिये, क्योंकि आने वाले वक्त में फूड कारपोरेशन को एक ऐतिहासिक रोल भ्रदा करना है। इस तरह के जितने भी कारपोरेशन हमारे देश में बनाये गये हैं, दुर्भाग्य से उन सब के सलाहकार प्राइवेट सेक्टर से ला कर रखे गये। इसका नतीजा यह हुआ कि पब्लिक सेक्टर उतना नहीं बढ़ सका जितना कि बढ़ना चाहिये।

आज कल जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के रास्ते में जो लोग रोड़े धरते हैं, वह यह आड़ती लोग हैं और वही जागीरदारी के चौकीदार बन गये हैं क्योंकि उन लोगों की गढ़ियों में आड़तियों को छपना माल रखने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूँ कि फूड जोन इस देश में खत्म कर दिये जायें क्योंकि अगर आड़तियों को मौका दिया गया तो यह लोग मनुष्यत्व लोगों को भूखों मार देंगे। आज इन आड़तियों के मुँह में मुनाफे का इतना खून लग चुका है कि यह लोग खुद भूखों मर लेंगे लेकिन अनाज जरूर गाड़ कर रखेंगे। मैली धोती पहनेंगे, मैली बनियान पहनेंगे लेकिन उनके पास करोड़ों रुपया होगा। उसके बावजूद भी अगर अनाज की कमी होगी तो उसको उन्होंने छपने गोदामों में भर कर रखा हुआ होगा। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों से बचाने के लिये, गरीब जनता को बचाने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाये। आड़तियों का होना देश के लिये एक दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को सजा दी जाये जो इस तरह से होड़िंग करके मास को अपने वहाँ छिपाये रखते हैं।

## श्री इत्तहाक साबन्वी (अमरोहा) :

मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ जो मेरे मधु-कुंवर मोहन स्वरूप जी ने पेश किया है। चूंकि वक्त बहुत कम है इस वास्ते मैं इतनी ही पुकारिश करता हूँ कि चले की क्लेड आड़तियों की अक्स में एक जलजल बन कर रह गई है। एक तरफ तो ये आड़ती

किसानों को लूटते हैं और दूसरी तरफ कंजूमर्स को लूटते हैं। मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि जितना बैकवर्ड एरिया हो जितने गरीब किसान हों उतना ही ज्यादा उनको सूटा जाता है। मंडी में भ्रमर किमान गल्ला लगता है तो खीर झाड़नी की दलाली से उसको वह बेच नहीं सकता है। उसकी गाड़ी जब झाड़ती के यहां पहुंचती है तो आप देखें कि उससे कितना ही पैसा धर्म-खातों के नाम पर बसूल किया जाता है। कहा जाता है कि यह गोशाला के लिये खाता है, यह मंदिर के लिये खाता है, यह विधवा धर्म खाता है और न जाने कितने नामों में उन्होंने ये खाते खोल रखे हैं। यह कहा जाता है कि बिरला जी बड़े भारी दानी हैं या फलां झाड़नी बड़ा भारी दानी है और बहुत पुण्य करता है। लेकिन किस से पैसा ले कर यह पुण्य किया जाता है। इनके पैसों से ही तो यह किया जाता है। इनका पैसा ही तो लूटवाया जाता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उम पैस से पोलिटिकल पार्टीज तक की मदद की जाती है। किसान को एक्सप्लायट करके जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वही पैसा तो यहां खर्च किया जाता है। कंजूमर्स का भी इसी तरह से एक्सप्लायटेशन होता है।

मेरे खयाल में मेरे भाई अपनी कांस्टिट्यूएन्सी में जो धाड़ लोग कहलाते हैं जल्दी में उनकी बात को कहना भूल गये हैं। पीलीभीत और नेपाल की तराई में वे रहते हैं। इन बेचारे धाड़ुओं के लिये ये झाड़नी सिर्फ मिट्टी का खेत और खाने के लिये थोड़ा सा चावल छोड़ देते हैं बाकी सब का सब उनसे वसूल कर लेते हैं। उनके बच्चे कर्जदार पैदा होते हैं और कर्जदार मरते हैं। एक तरफ तो किमानों की यह सूट चलती है इनकी तरफ से और किसानों को तबाह और बरबाद जिन्दगी के लिये कर दिया जाता है और दूसरी तरफ क्या होता है इसको भी आप देखें। मेरे अपने जिले का बाका है कि 25 से 28 रुपये मन तक इन झाड़तियों ने किसानों से गल्ला खरीदा और उसको 60 रुपये मन से

लेकर 66 रुपये मन तक के भ्रव पर बेचा। क्या इस बात को भुलाया जा सकता है कि जब जिला बनारस में—मुजफ्फरपुर में और बिहार में लोग भूखों मर रहे थे एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे रहे थे उस वक्त इन झाड़तियों के मकानों में चावल की बोरेबां, घाटे की बोरेबां छतों में बातों कर रही थीं।

इतना होने पर भी आज यहां पर इनको बर्कालत की जाती है। इस बात पर गौर नहीं किया जाता है कि इनके खरिये से इस मुल्क को किनना नुकसान हो रहा है, कितनी तबाही हो रही है। गल्ले का ब्यापार हमारे मुल्क का सब से बड़ा ब्यापार है। लगभग दस करोड़ टन गल्ला इस मुल्क में खरीदा और बेचा जाता है जिस पर लगभग पांच अरब रुपये से ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। यह जो मुनाफा है यह काम के काम में भ्राना चाहिये।

मैं मानता हूँ कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में बहुत बुराईयां हैं बहुत ज्यादाियां हानो हैं बुरे काम होते हैं बड़ा नाम होता है। हमारे बुजुर्गोंको प्रभु साहब ने कहा कि यह पब्लिक का ही तो नुकसान होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में जो कमियां हैं, उनको दूर करना भी तो हमारा फर्ज है। जब उसकी बात आयेंगी तो उसको भी हम सचता के साथ फिटिलाइज करेंगे। उसको हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि चाहे कोई सरकारी इदारा हो या गैर सरकारी तीस रुपये मन गल्ला खरीद कर 66 रुपये मन बेचें या इस इंतजार में रहे कि कब कल्ला महंगा हो और कब बेचा जाये। लोग भूखों मरते रहें लेकिन वह इस गल्ले को वचा कर बैठा रहे।

मैं दरदबास्त करना हूँ कि इसको पार्टी के मुक्ते नजर से न देखा जाये। इस तरह से न देखा जाये कि सुंवर मोहन स्वल्प जो जिस पार्टी से माल्लुक रखते हैं उस पार्टी की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। मैं चाहता हूँ कि पार्टी

## [श्री इसाहाक साम्भल]

लैंडल से ऊपर उठ कर हम को इस प्रस्ताव को एक राय से पास कर देना चाहिये । मैं यह भी चाहता हूँ कि सरकार तेजा के साथ इस तरफ कदम बढ़ाये । अगर वह ऐसा न करेगी तो एक तरफ तो कंजूमस को और दूसरी तरफ किसानों को लूट इसी तरह से चलता रहेगा । मुझे तो कई बार शुकवा होता है और यह एक कुदरती बात भी है कि कहीं सरकार को भी उन व्यापारियों के साथ मिलो भगत तो नहीं है । इतलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस रेजाल्यूशन का इतिफाके राय से पास किया जाये और गल्ले की तिजारत को फोरो तीर पर नेशनलाइज किया जाये ।

## [श्री अस्तक सधेली (अमरोहा) :

मैं इस प्रस्ताव का प्रेरणक हूँ । मैं समझता हूँ कि सरकार को इस प्रस्ताव को पास कर देना चाहिए । मैं यह भी चाहता हूँ कि सरकार तेजा के साथ इस तरफ कदम बढ़ाये । अगर वह ऐसा न करेगी तो एक तरफ तो कंजूमस को और दूसरी तरफ किसानों को लूट इसी तरह से चलता रहेगा । मुझे तो कई बार शुकवा होता है और यह एक कुदरती बात भी है कि कहीं सरकार को भी उन व्यापारियों के साथ मिलो भगत तो नहीं है । इतलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस रेजाल्यूशन का इतिफाके राय से पास किया जाये और गल्ले की तिजारत को फोरो तीर पर नेशनलाइज किया जाये ।

मैं इस प्रस्ताव का प्रेरणक हूँ । मैं समझता हूँ कि सरकार को इस प्रस्ताव को पास कर देना चाहिए । मैं यह भी चाहता हूँ कि सरकार तेजा के साथ इस तरफ कदम बढ़ाये । अगर वह ऐसा न करेगी तो एक तरफ तो कंजूमस को और दूसरी तरफ किसानों को लूट इसी तरह से चलता रहेगा । मुझे तो कई बार शुकवा होता है और यह एक कुदरती बात भी है कि कहीं सरकार को भी उन व्यापारियों के साथ मिलो भगत तो नहीं है । इतलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस रेजाल्यूशन का इतिफाके राय से पास किया जाये और गल्ले की तिजारत को फोरो तीर पर नेशनलाइज किया जाये ।

कहना है, ये मंदर के लूँ केहता है - ५,  
 उधर उधर के लूँ केहता है और न जाने  
 कितने नामों से अन्धों ने ये केहते केहल  
 रके हैं - ये केहा जाता है के भला जी  
 भूँ केहारी दानी हैं - या फल आरुती  
 भूँ केहारी दानी है और बेत पले केहना  
 है - लेकिन कस से पेसे ले के पले,  
 केहा जाता है - मैं तो येहा तक केहना  
 के अस पेसे से पोलिटेकल पारटिज तक  
 की मदद की जाती है - कसान को  
 अक्सिडेंट के के जो पेसे अकथा केहा  
 जाता है ही पेसे तो येहा खर्च केहा  
 जाता है - कल्टिवेमेन्ट का भी असी तरह से  
 अक्सिडेंटलेशर रता है -

मैं इस प्रस्ताव का प्रेरणक हूँ । मैं समझता हूँ कि सरकार को इस प्रस्ताव को पास कर देना चाहिए । मैं यह भी चाहता हूँ कि सरकार तेजा के साथ इस तरफ कदम बढ़ाये । अगर वह ऐसा न करेगी तो एक तरफ तो कंजूमस को और दूसरी तरफ किसानों को लूट इसी तरह से चलता रहेगा । मुझे तो कई बार शुकवा होता है और यह एक कुदरती बात भी है कि कहीं सरकार को भी उन व्यापारियों के साथ मिलो भगत तो नहीं है । इतलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस रेजाल्यूशन का इतिफाके राय से पास किया जाये और गल्ले की तिजारत को फोरो तीर पर नेशनलाइज किया जाये ।

मैं इस प्रस्ताव का प्रेरणक हूँ । मैं समझता हूँ कि सरकार को इस प्रस्ताव को पास कर देना चाहिए । मैं यह भी चाहता हूँ कि सरकार तेजा के साथ इस तरफ कदम बढ़ाये । अगर वह ऐसा न करेगी तो एक तरफ तो कंजूमस को और दूसरी तरफ किसानों को लूट इसी तरह से चलता रहेगा । मुझे तो कई बार शुकवा होता है और यह एक कुदरती बात भी है कि कहीं सरकार को भी उन व्यापारियों के साथ मिलो भगत तो नहीं है । इतलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस रेजाल्यूशन का इतिफाके राय से पास किया जाये और गल्ले की तिजारत को फोरो तीर पर नेशनलाइज किया जाये ।

روپے من تک ان آڑھتوں نے کسانوں سے غلہ خریدالو اس کو ۶۰ روپے من سے لے کر ۶۶ روپے من تک کے پہاؤ پر بھیجا۔ کہا اس بات کو بھیایا جا سکتا ہے کہ جب مباح ہمارے میں مظاہر پور میں اور بہار میں لوگ بھوکوں مردہ تھے۔ اہڑیاں رگہ رگہ کر جان دے رہے تھے اس وقت ان آڑھتوں کے مکانوں میں چاول کی بوریاں۔ آئے کی بوریاں چھتوں سے باتیں کر رہی تھیں۔

اتنا ہونے پر بھی آج ان کی یہاں وکالت کی جاتی ہے۔ اس بات پر غور نہیں کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اس ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ کلمی تھامی ہو رہی ہے۔ غلے کا بیویار ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیویار ہے۔ لگ بھگ دس کروڑ تین لاکھ اس ملک میں خریدتا اور بھیجا جاتا ہے جس پر لگ بھگ پانچ ارب روپے سے زیادہ مباح کیا جاتا ہے۔ یہ جو مباح ہے یہ قوم کے کام میں آنا چاہئے۔

میں مانتا ہوں کہ سٹیٹ ٹریڈنگ میں بہت خریدیں ہیں۔ بہت زیادتیں ہوتی ہیں۔ برے کام ہوتے ہیں، بڑا اس ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ لوگوں پر یہو صاحب نے کہا کہ یہ ملک کا ہے تو نقصان دہتا ہے۔ لیکن میں لہذا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشن میں جو کمبل ہوں ان کو دور کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے جب

اس کی بات آئیگی تو اسکو بھی ہم سہتی کے ساتھ کرینگے سائز کرینگے۔ اس کو ہم محتاف نہیں کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چاہے کوئی سرکاری ادارہ ہو یا غیر سرکاری۔ تھیں روپے من غلہ خرید کر ۶۶ روپے من بھیجے یا اس انتظار میں رہے کہ کب غلہ پہنچا ہو اور کب بھیجا جائے۔ لوگ بھوکوں مرتے رہیں لیکن یہ اس غلے کو دبا کر بیٹھا رہے۔

میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو پارٹی کے نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے۔ اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ کلور موہن سرورپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس پارٹی کی طرف سے یہ پرستار آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پارٹی لہول سے اوپر اٹھ کر ہم کو اس پرستار کو ایک رائے سے پاس کر دینا چاہئے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سرکار تھوں کے ساتھ اس طرف قدم بڑھائے۔

اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک طرف تو کارڈوہ مرز کی اور دوسری طرف کسانوں کی لوٹ اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ مجھے تو کئی بار شہہ ہوتا ہے اور یہ ایک قدرتی بات بھی ہے کہ کہیں۔۔۔ کار کی یہی ان بیویاریوں کے ساتھ ملی بھگت تو نہیں ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس دہزولہوشن کے اتمام رائے سے پاس

[شرو استعاضی سبیلی]  
 کہا جائے اور غلے کی تجارت کو  
 فروغ طور پر نشہلائیں کہا جائے -

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) :  
 सभापति महोदय मैं एक किसान भी हूँ और उपभोक्ता भी हूँ और सरकार और व्यापारी दोनों का शिकार भी हूँ। जब मुल्क में कमी होती है गल्ले की तब तो दूसरी बात है लेकिन जब मुल्क में गल्ले का भाव चौदह रुपये मन था और गल्ला ज्यादा पैदा होता था उस वक्त सरकार ने कहा था कि नौ रुपये मन के भाव पर वह मंडी में गल्ले को खरीदेगी। लेकिन उसने आदेश दे दिया कि पांच नौ मन से अधिक बहन नहीं खरीदेगी। जब किमान की गाड़ी मंडी में आई तो लाला ने कहा कि चौधरी तुम्हारा भाल सरकार नहीं ले रही है यह जायेगा सात रुपये मन में। एक तो सरकार का यह हिमाब हमने देखा है।

उसके बाद जाकर 1965 में जब हमने देखा कि गल्ले की कमी है तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मुल्क को जरूरत है बेच दो और जाइँ में जाकर मक्का खरीद में। मेरी पत्नी ने बहुत इन्कार किया कहा कि न तो यह बढ़िया सरकार है और न ही बढ़िया व्यापारी है इस वास्ते साल भर का तो कम से कम खाने के लिए रख लो। लेकिन चूँकि मुल्क को जरूरत थी इस वास्ते उसको मैंने बेच दिया। जब मक्का निकला तो जितने रुपये मन के भाव पर गेहूँ बेचा गया था मन् 1966 के जाइँ में मक्का खरीदा तो उतने ही रुपये में तीस मेर मिला। गेहूँ का तो मक्का हो गया और वजन में भी घट गया। यह काम व्यापारियों ने किया।

हालत यह है कि जिस मुल्क में पैदा करने वाले आदमी को कम पैसा मिलेगा

और उसके उत्पादन के बेचने वाले अधिक पैसा मिलेगा उस मुल्क में बुद्धिमान आदमी भी चुस्त और चालाक होगा और उत्पाद में नहीं लगेगा, बेचने की तिकड़म में लग जायेगा। जिस मुल्क की बुँ बेचने में खर्च होने लगेगी उत्पादन में नहीं लगेगी वह मुल्क कंगाल होता चला जाएगा। वही आज मुल्क की हालत होती जा रही है। जब भी कोई काम तय किये जाते हैं तो किमान और उपभोक्ता दोनों की जो प्रमहाय म्बिति है उसका अनुचित लाभ उठाकर तय कर दिये जाते हैं, अनचित लाभ उठा कर तय कर दिये जाते हैं। सरकार भी जब तय करती है तब भी यही हिसाब लगाती है कि इतना मूल्य मिल जायेगा या नहीं मिलेगा। उम की जो उत्पादन कीमत है उसकी जो लागत कीमत है उसका भी तो हिसाब लगाया जाना चाहिये लेकिन वह कभी नहीं लगाया जाता है।

हमारे जब संघ वाले और स्वतन्त्र पार्टी वाले इसको कुछ आइड्योलोजिकल सवाल बना रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि यह कोई आइड्योलोजिकल सवाल है। जापान में मुक्त व्यापार है। वहाँ तो पूँजीवादी प्रर्थ व्यवस्था है। लेकिन प्राप देखें कि वहाँ भी फूड की ट्रेड नेशनलाइज्ड है। प्रापकी की ट्रेड का फ्री इंटरप्राइज का सब से बड़ा जो लकड़दादा अमरीका है वहाँ भी व्यापारी पूरी तरह से इस ट्रेड को नहीं ले पाया है। एक मार कर वहाँ सरकार को यह काम करना पड़ता है कि इस सीमा से नीचे प्रागर कीमतें गिरती हैं तो लाखों टन गल्ला सरकार खरीदती है और ऊपर जब कीमतें जाती हैं तो उम गल्ले को बेचती है। पूँजीवाद के द्वारा तो इस मसले को हल किया ही नहीं जा सकता है। सरकार को तो बीच में आना ही पड़ता है अमरीका में भी और जापान में भी।

इसेलि में चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन हो और ध्यान भी इसको समर्थन प्रदान करें ।

MR. CHAIRMAN: The word *lakad dada* is not in good taste. Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): Mr. Chairman, I thank Shri Mohan Swarup for moving his Resolution on a subject which vitally concerns the life of our people and I appreciate the sentiments expressed by Shri Mohan Swarup and by many of the hon. Members who have expressed their views on the floor of the House. Shri Maharaj Singh Bharati just now referred to the fact that even in a country like Japan there is intervention by Government in food trade. Not only in Japan, but if we examine the trade pattern of many other countries, Italy for instance, we find the paddy trade in Italy is in the hands of the State. So, State intervention is there. Not only in the deficit countries but even in surplus countries like Canada and Australia there is the Wheat Board. Both those countries are surplus from the point of view of wheat production. But even then there is intervention from the State both in the internal trade as well as in the external trade.

SHRI LOBO PRABHU: No control; only purchase.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In a vast country like that of India which is deficit to a certain extent in regard to food, I do not think we can allow *laissez faire* in regard to the food trade.

SHRI PILOO MODY: What is that?

SHRI LOBO PRABHU: Let go.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In fact, a number of expert committees,

which have examined this aspect, have also come to the same conclusion. For instance, after the tragedy of 1943 of the Bengal famine, the then Government of India appointed a famine commission to go into the food problem. I do not think even friends of the Swatantra Party or the Jana Sangh will allege that at that time the Government was having any ideological inclinations. But even then the Famine Commission, which submitted its report in 1945, came to the conclusion that to provide food is mainly the responsibility of Government and that Government must intervene in the food trade if it is to provide protection to the people.

So, as far as the point whether Government should interfere in the food trade or not is concerned, it is the primary responsibility of Government to see that foodgrains are made available at a reasonable price to the people at large. Therefore Government must necessarily intervene in the food trade. So, I do not at all agree with the views expressed by Shri Lobo Prabhu and Shri Sharma of the Jana Sangh.

But, at the same time, there are various other aspects of the problem too. Some hon. Members have referred to the problem from the point of view of how the farmer should be assured of a reasonable price. That also is a very important point. The usual phenomenon of trade in this country has been that in the immediate post-harvest period prices get depressed and farmers are left at the mercy of the trading community and as soon as the lean period comes the consumers have to purchase the same foodgrains at a very high price and they are left at the mercy of traders. This is a phenomenon repeated from year to year.

SHRI LOBO PRABHU: You have the powers to acquire and licence grain. What are you doing for acquiring the hoards of foodgrains with traders? Please explain that. The fault is yours.

**SHRI ANNASAHIB SHINDE:** Not only from the point of view of Government's responsibility or of Government intervening in the food trade but even from the point of view of assuring remunerative or reasonable prices to the farmers and, at the same time, ensuring availability of foodgrains to the consumers at reasonable prices, I think, Government owes some responsibility and in our country we have to develop public sector agency which will take care of this.

So, as far as the general sentiment expressed by hon. Member Shri Mohan Swarup is concerned, I am completely in agreement with him. But I do not share the sentiment of some hon. Members who from the ideological point of view say that everything should be nationalised. I do not agree with that view also; but, at the same time, we should not have an allergy as some Swatantra Members are allergic. Whenever the word 'nationalisation' or 'socialisation' of food trade comes in, they are very allergic.

**SHRI PILOO MODY:** The very fact that you mention that the Government must interfere is in itself a very unfortunate choice of words. What you should say is "regulate" and not "interfere".

**SHRI ANNASAHIB SHINDE:** But we have to take a practical view in this matter. In our country we must proceed on the assumption that we must develop a public sector organisation and to see that the public sector organisation gets a commanding position in the food trade. That is why the Government of India established the Food Corporation of India and the Food Corporation of India is for the first time in a very big way in the food trade. We have been assuring the farmers now that we shall be prepared to purchase foodgrains not only at the minimum price or the support price but we shall be purchasing foodgrains at the procurement price.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA** (Delhi Sadar): Can you give the firm

assurance to the farmers that you will not reduce the procurement price?

**SHRI ANNASAHIB SHINDE:** May I assure Shri Gupta, this House and the farmers of this country that we stand firm by this that we shall be prepared to purchase any quantity offered by farmers at the procurement price. That is why the State Bank of India has placed about Rs. 120 crores at the disposal of the Food Corporation of India. Moreover, in addition to that, Rs. 39 crores have been advanced to the Food Corporation of India by way of loans, and in this Budget also which is before the House, about Rs. 40 crores have been provided so that, as and when it requires, the amount may be made available to the Corporation. So, we should see that the Food Corporation really gets a commanding position in the food trade. But the difficulty in this country is that we have to see that public opinion is educated so that the public sector organisation really gets necessary cooperation from the various State Governments from the public bodies and from the various parties as such.

I would appeal to the House and to the Members of the Swatantra Party and Jana Sangh, particularly, that they should not have ideological bias against this because the Government do not proceed on the assumption of any ideological bias as such but take into consideration the vital interest of the masses and the farmers and the food economy of the country because stabilisation of food economy is very important. I hope all the Members of the House will give necessary cooperation to the Government of India and see, in times to come, that the Food Corporation plays a very important role in our country, I wish to extend the same appeal to the various State Governments.

**SHRI LOBO PRABHU:** Why don't you take the trouble of giving the

reason why you disagree with my proposition? I put a very clear proposition. You create artificial scarcity, you create high prices and you are the cause of the food problem in the country. Please answer that question.

**SHRI ANNASAHIB SHINDE:** I have already covered his point. Free trade was having full play in this country. There was no curb on free trade and that led to this phenomenon. That is why if the Food Corporation comes more and more in the food trade, all these things can be eliminated.

**SHRI SONAVANE (Pandharpur):** It was because of the free trade that these people fleeced the farmers and the consumers.

**SHRI ANNASAHIB SHINDE:** I would appeal to the hon. Member to withdraw the Resolution, not to press for it because I have expressed my views and the Government shares his sentiments. At the same time, it is not necessary to press this Resolution because it will not serve any purpose. I do not think the stage has come when we can really do anything more than what the Government is already doing in the field.

**श्री इसहाक साहबजी:** वह टाइम कब आयेगा, जब लूट-खसोट बन्द की जायेगी ?

**श्री मोहन स्वरूप :** सभापति महोदय, मैं अपने दोस्तों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ ही साथी दूसरे दोस्तों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इसमें भाग लिया—चाहे वे इस तरफ के हों या काँग्रेस की तरफ के लोग हों। हर आदमी यह पसन्द करेगा कि कीमतें बढ़ने से रोकੀ जाए, साथ ही साथ यह भी चाहेगा कि बाहर से हम गन्ता आयाता न करें—चाहे लीतो प्रभू हों या दूसरे लोग हों। हर आदमी आज यह भी चाहेगा कि किसानों को उसकी पैदावार का,

उसकी उपज का उचित भाग मिले। लेकिन मैं कह सकता हूँ, सभापति महोदय, जो स्थिति इस वक्त चल रही है, जैसा कि मेरे दोस्त ने यहाँ पर नक्शा खींचा, मैं समय के अभाव के कारण वह नहीं कह सका। इस स्थिति में भी किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसान एक ऐसी भेड़ के समान है, जिस को जो चाहता मूड़ लेता है।

दूसरी बात—किसान इस वक्त देश में संगठित नहीं हैं उस को संगठित होने से रोका गया है। चाहे कोई भी जमाना आया—अंग्रेजों का जमाना आया या काँग्रेस का जमाना आया—किसान को संगठित होने से सदैव रोका जाता है, क्योंकि सरकार डरती है कि अगर ये संगठित हो गये तो वह एक ऐसी शक्ति होगी, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। लेकिन अब वक्त आ रहा है, किसानों में चेतना आ रही है और अब वह समय दूर नहीं है जबकि वह संगठित हो कर रहेगा। जैसा मैंने अभी अर्ज किया था—किसान ही एक ऐसा बदनसोब तबका है इस समाज में, जिस को कि अपनी उपज का मूल्य निर्धारित करने का स्वयं अधिकार नहीं है। लेकिन अब वह समय आ रहा है, शायद बहुत जल्द आयेगा, जब कि किसान संगठित होंगे और उन को अपना पेट भरने का, अपनी रीट ह सिल करने का हक उन्हें प्राप्त होगा।

जो वर्तमान स्थिति चल रही है उस से काम चलने वाला नहीं है। मैं शिंडे साहब और सरकार से अनुरोध करूँगा कि वे राष्ट्रीयकरण की तरफ पग बढ़ायें क्योंकि यह केंसर जैसी पुरानी बीमारी हो गई है जिसको काट डालने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं ज्यादा समय न लेकर केवल

[श्री मोहन स्वहा]

यही अनुरोध करता कि जो मेरा प्रस्ताव है उसको स्वीकार करने की कृपा करें और उसे कार्यान्वित करने की बात सोचें, तभी किसानों और उपभोक्ता दोनों का लाभ हो सकता है।

**SHRI ANNASAHIB SHINDE:** I appeal to the hon. Member not to press his Resolution.

**MR. CHAIRMAN:** Is he willing to withdraw his Resolution?

**सभापति महोदय :** क्या आप प्रस्ताव को वापिस करना चाहते हैं ?

**श्री मोहन स्वहा :** मन्त्री जी के इस आश्वासन के बाद कि वे गम्भीरता से इस पर विचार करेंगे, मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ।

**MR. CHAIRMAN:** Has he the leave of the House to withdraw his Resolution?

**SEVERAL HON. MEMBERS:** Yes.

*The Resolution was, by leave,  
withdrawn.*

**MR. CHAIRMAN:** The next Resolution is that of Mr. N. K. Somani.

About the fourth Resolution, I want to make this clear. The Second Resolution was started, at 4.40; even if it had been completed within one hour, the Fourth Resolution could not come because now Mr. Somani's Resolution is there and then at 6.30 we have got a half-an-hour discussion.

**SHRI S. XAVIER:** I shall just move it, Sir.

**MR. CHAIRMAN:** Unless Mr. Somani's Resolution is disposed of, how can that be taken up?

**SHRI LOBO PRABHU:** He may just be allowed to move his Resolution and he can continue on the next

occasion. That is an important Resolution.

**MR. CHAIRMAN:** But Mr. Somani's Resolution has to be disposed of and then only it can be taken up.

**SHRI N. K. SOMANI (Nagaur):** After my Resolution, you may allow him just to move.

**SHRI PILOO MODY:** If Mr. Somani's Resolution is finished by 6.25 P.M., then Mr. Xavier can be allowed to move his Resolution.

**MR. CHAIRMAN:** Even if it finishes at 6.30, I have no objection to Mr. Xavier moving his Resolution. I do agree that it is a very important Resolution.

Now Mr. Somani.

17.52 hrs.

**RESOLUTION RE: REMOVAL OF  
ZONAL RESTRICTIONS ON MOVE-  
MENT OF FOODGRAINS**

**SHRI N. K. SOMANI (Nagaur):** I beg to move:

"This House is of opinion that in view of increased food production during the current year, zonal restrictions on the movement of foodgrains be removed forthwith."

We have heard from almost all the speakers who participated in the previous Resolution that food is an item or a subject of discussion which should not have any ideological barriers or should not have State or party barriers. But unfortunately from what we have seen and from what has been the experience in the last few years, one is constrained to come to the conclusion that even in regard to such a vulnerable, such a needy, such